32. प्रबंध निदेशक,
सन्नी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०,
कलकत्ता–700025

33. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कोलफेक्स लेब्रोटोरीज इंडिया प्रा० लि०, फोण्डा, गोवा ।

34. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कासमेटिक एंड टोइलेट कारपोरेशन, 3 के बी लेन,
कलकत्ता–37

35. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स विक्को लेब्रोटोरीज,
12, धरम पुत्र,
डा० अम्बेदकर रोड, दादर,
बम्बई–400014

36. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स इंडियन कासमेटिक,
35/जे, राजा नवा कृष्णन स्ट्रीट,
कलकत्ता–70005

37. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स पिडीलिटी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
बम्बई–400021

38. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स अम्रतांजन लि०, 42–45,
लुज चुओल रोड, मद्रास–600004

39. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कोठारी प्रोडक्टस प्रा०लि०,
24/19, थेमाल्ल, कानपुर – 208006.

High Level Committee on the ICAR

2448. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of the members including its Chairman of the High Level Committee which was set up some time back to examine the working of ICAR and what is the terms of Office of the Chairman; and

(b) by when a report is likely to be submitted by he siad Commitee?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The matter is under consideration and details will be furnished as soon it is finalised.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का सुझाव

2449. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1986 में सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद्, आलमबाग, लखनऊ के अध्यक्ष की ओर से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां । परिषद् की कुछ मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(i) उचित दर की दुकानों के मालिकों के मार्जिन में वृद्धि की जाए ।

(ii) बैंक ड्राफ्ट के कमीशन का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए ।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(iv) उचित दर की दुकान के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही केवल तभी आरम्भ की जाए जब कोई विशेष आरोप प्रमाणित हो जाए ।

(v) एक उचित दर की दुकान के लिए कम से कम 4000 यूनिटों का आवंटन किया जाए ।

(vi) उचित दर की दुकानों को बैंक ऋण देने की व्यवस्था की जाए ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर समय-समय पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि उचित दर की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें । उनसे कहा गया है कि वे विनिर्माताओं से उन अन्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति स्वयं करें, जिन्हें वे उचित दर की दुकानों के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता में वितरित कर सकती हैं । इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने तथा उचित दर की दुकानों में खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होने के के कारण, उन्हें दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे हर 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान खोलने के आधार पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाएं । इस संबंध में छितरी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में जहां इस मानदंड को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है, छूट दी जा सकती है । राज्य सरकारें, प्राप्त हुई शिकायतों की जांच के आधार पर उचित दर की दुकानों के मालिकों के खिलाफ समय-समय पर कार्यवाही करती हैं । चूंकि आवश्यक वस्तुओं का कारोबार करने वाली उचित दर की दुकानें प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि वे उचित दर की दुकानों के मालिकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त ऋण सुविधाएं दिलवाने के लिए प्रबंध करें ।

सरकारी कालोनियों में सफाई

2450. श्री रामचन्द्र विकल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सरकार कालोनियों ; सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या कुछ कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस कार्य को ठेकेदारों से ठेके पर कराता है, यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह कार्य कुछ पूछताछ में "हैंड रसीद" पर भर्ती कर्मचारियों से कराया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को धक्का लगा है और इससे न केवल अनुसूचित जातियों के लोगों में बेरोजगारी ही बढ़ी है बल्कि सफाई व्यवस्था में भी गिरावट आई है ; और

(ङ) सरकार इस कार्य को ठेकेदारों से कराने की प्रथा को कब तक खत्म करने तथा इसे नियमित आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों से कराने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Inadequate pasture land near Ranthombore Park

2451. PROF. C. LAKSHMANNA:
SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of villages surrounding the Ranthombore Park area in Rajasthan have not adequate pastures lawn for their cattle numbering about 40,000; and

(b) if so, whether Government have taken any measures to provide adequate fodder to the villages for their cattle so that the Ranthombore National Park area is not damaged by the villagers?